ہے کہ اس طرح کے اشیو نہیں لئے جائینگے تو بڑ مشکل ہو جائیگا۔

उपसभापति : मुझे मालूम नहीं हैं। मैं इसके बारे में मालूम करके मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी।

RE. ALLOTMENT OF STALLS TO PEPSI AT NEW DELHI RAILWAY STATION IN PREFERENCE TO A PUBLIC SECTOR UNIT

SHRI JAGESH DESAI (Maharasht ra): Madam Deputy Chairman, I want to raise an important issue. I am happy that some time back, our Industry Minister, Shri Karunakaranji, made a statement and reiterated that Government would not allow any public sector unit to be privatised and wherever sick units were there, he would make all efforts to revive them. I am very happy about it. We should take action on that line. *Interrup tions.)*

SHRI M.A. BABY (Kerala): Words are very good. What about deeds?

The Vice-Chairman (Shri Suresh Pachouri) In the Chair.

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Vice-Chairman, we want the food-processing industry to be given more fillip, more advantage and more encouragement. But what happened? The Minister for Food-Processing Industries, Mr. Tarun Gogoi, wrote a letter to the Railway Minister. I am reading out from that letter. "I wish to take this opportunity to introduce the Modern Food Industries Limited, a Government of India Undertaking." That means, a public sector undertaking. "They should be allowed a stall on platform No. 10 for mango juice which they are giving by vending machines." It costs only Rs. 3/-. Unfortunately, after the letter was written by the Minister, on 21st September, 1994, the Private Secretary to the Minister of Railways wrote back stating that it was being looked into. A second reminder was sent. *(Interruptions).*

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): The reply was sent by the Private Secretary?

SHRI JAGESH DESAI: Yes. It was sent by the Private Secretary. I am sorry to report that instead of giving a stall to the public sector food-processing unit, three stalls were given, not one, on platform No. 10 in the New Delhi Railway Station, to the Pepsi Company. It was' not given to our public sector company. How did it happen? I was always taking this juice because it would cost only Rs. 3/- per glass whereas Pepsi would cost Rs. 6/- or Rs. 7/- a glass. When I enquired, "Why should you not have a mango juice stall there?" I told them, "The Rajdhani Express leaves from platform No. 10. Why don't you have a stall on platform No. 10? In reply to that, it was said that they had already written in 1994. The public sector undertaking was not given any stall. And three stalls have been given to multinationals! Are we going to have multinationals or are we going to have public sector units? The sickness of our public sector is because of such reasons. If you want the public sector is to thrive, at least one stall should have been given to them. Let people take what they want, whether mango juice or Pepsi. Let it be left to them. Unfortunately, orders are not being received by the public sector units and many public sector units are becoming sick because they are not getting the orders. This was a small thing and even the Minister had written about it. I made enquiries with the Minister's office and I was given to understand that an enquiry has been made. But those who are sitting in the Baroda House have not cared even to furnish the enquiry report to the minister. If the report had been submitted to the Railway Minister, I am sure, the Railway Minister definitely would have

given it to the public sector. But, unfortunately, those who are sitting in the Baroda House, are not doing it. I would like the Minister to explain to us as to how it happened. I would also request him to make an enquiry and find out whether any illegal things were done because the public sector did not give any money. Others might have given. That is why I condemn it and I want an enquiry to be made into this matter.

श्री चतुरानन मिश्र (**बिहार**) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही प्रतिष्ठित माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया हैं। अगर्चे उन्होने प्लेटफार्म पर तीन स्टाल्ज के बारे में सवाल उठाया हैं लेकिन हमको लगता हैं कि जब मुल्क ही दिया जा रहा हैं मल्टीनेशनलज को, प्लेटफार्म का हम लोग क्या करें? लेकिन फिर भी मैं एक बात जानना चाहता हूं, वह यह हैं कि विपक्ष में और सरकारी पार्टी में ...(**व्यवधान**)....

All right. Mr. Finance Minister, I am telling you.

SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA (Uttar Pradesh): He belongs to the CPI and not to the CPI(M).

SHRI CHATURANAN MISHRA: I am telling you that there is a difference between Jyoti Basu and you and the basic difference is that perhaps there are no two opinions about the multinational coming in certain sectors. But, in respect of food, drinks and consumer goods, we do not want them. This is the difference between you and Jyoti Basu because you have raised it.

मैं आपसे कहना चाहता था कि शासक पार्टी का इतिहास हैं देश की आजादी की लड़ाई लड़ने और उस शासक पार्टी के बारे में धारणा हो रही हैं कि मुल्क को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में बेच रहे हैं। क्यों आप फूड एंड ड्रिंक्स में भी सत्ती होना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज पर, हम को समझ में नहीं आ रहा हैं। जब विपक्ष भी आपका साथ दे रहा हैं सर्टेन सेक्टर्ज में जहां जरूरी हैं हम जाएं। लेकिन ख्वामखाह आप सती होने के लिए क्यों जा रहे हैं जिसको लार्ड विलियम बैटिक ने गैर कानूनी कर दिया था। उसको आप फिर रिवाइव क्यों कर रहे हैं यह मुझे आपसे प्रश्न पूछना हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं जागेश देसाई जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होने कांग्रेस की परंपरा को याद करते हुए अपनी बात को सही ढंग से रखने की कोशिश की और मनमोहन सिंह जी अगर आप अभी भी उनकी बात समझ ले तों देश में बहुत बुरी हालत होने वाली नहीं हैं ...(**व्यवधान**)....

SHRI JAGESH DESAI: This is not a question of policy. This is a question of encouraging the public sector.

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले पूरे सदन सर्वसम्मति से अपनी राय जाहिर की थी और मारग्रेट आल्वा जी यहां बैठी हुई थी। उन्होने कहा था कि सदन की इस भावना से सरकार को अवगत करा दिया जाएगा। इन्ही सवालों से जुड़ा हुआ सवाल था कि इस देश में जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से खाने-पीने का समान बुलाया जा रहा हैं

केंटेकी फ्राइड चिकन से ले कर पेप्सी के जूस तक। इन सारी चीजों को इस देश में आने से रोका जाए। सारे सदन ने, चाहे किसी भी दल के लोग हों, सभी ने इसका समर्थन किया था। आज तक सरकार की तरफ से आपने प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश दिया, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिली हैं। मारग्रेट आल्वा जी ने सरकार की तरफ से यहां पर आश्वासन दिया था। यह रिकार्ड में हैं और सारे लोग मानते हैं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि सरकार सचमुच में उसके बारे में क्या कोई कदम उठाने जा रही हैं या मल्टी नेशनल्ज को केंटकी फ्राइड चिकन से ले कर पेप्सी के जूस तक आने की इजाजत दे रही है। ...(**व्यवधान**)....

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (**राजस्थान**) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जागेश देसाई जी ने जो सवाल उठाया हैं भोजन की सामग्री और ठंडे पेय, यह ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रवेश नहीं मिलना चाहिये। यह सवाल जो आप यहां उठाया गया हैं मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर जल्दी ध्यान दे कर इस व्यवस्था को ठीक करवाए।

डा. मुरली मनोहर जोशी (**उत्तर प्रदेश**) **:** मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि पेप्सी जो दो सौ रूपए किलोग्राम के हिसाब से पोटेटो चिप्स बेचती हैं वह भी स्टेशनों पर बेचने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। यह सदन नहीं चाहेगा कि दो रूपए किलोग्राम आलू खरीद जाए और दो सौ रूपए किलोग्राम पोटेटो चिप्स बेची जाए और मुनाफा मल्टी नेशनल कम्पनी बेहिसाब कमाती चली जाए। मैं

बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जो यह बात कहीं जा रही हैं इस पर पूरी रोक लगनी चाहिए और यह पैसा हिंदुस्तान के किसान को नहीं मिलता हैं। यह मल्टीनेशनल को मिल रहा हैं।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जगेश देसाई जी ने जो सवाल उठाया हैं पूरे सदन ने इसके साथ एसोसिएट किया हैं और सभी ने अपनी सहमति दी हैं। तो हम समझते हैं कि यहां जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद है वे जो सदन की भावना हैं उसे प्रधान मंत्री के पास रखें। वित्त मंत्री तो चले गए हैं। उनको आगे कदम उठाने के लिए कहा गया था कि पीछे कदम उठा गए।लेकिन मैं यह कहता हूं कि पेप्सी को जिस तरह से तवज्जह दी जा रही हैं, प्रायोरिटी दी जा रही हैं, प्राथमिकता दी जा रही हैं उसे तो कम से कम बंद करें। यह काफी मतलब निलर्ज्जता हैं।

†شری محمد سلیم "پشچمی بنگال": اپ سبھا ادھیکش مہودے۔ جگیش ڈیسائی جی نے جو سوال اٹھایا ہے پورے سدن نے اسکے ساتھ ایسوسی ایٹ کیا ہے اور سبھی نے اپنی سہمتی دی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جو پارلیمنٹری افیئرس منسٹر موجود ہیں وہ جو سدن کی بھاونا ہے ا سے پردھان منتری کے پاس رکھیں۔وت منتری تو چلے گئے ہیں انکو آگے قدم اٹھانے کیلئے کہا گیا تھا وہ پیچھے قدم اٹھا گئے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ "پیپسی" کو جسطرح سے توجہ دی جا رہی ہے۔ پرائرٹی دی جا رہی ہے ا سے توکم سے کم بند کریں یہ کافی مطلب نرلجتا ہے۔

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, मारग्रेट आल्वा जी यहां मौजूद हैं। दिग्विजय जी ने 29 मई को इस प्रश्न को उठाया था और उन्होने एश्योरेंस दिया था कि प्रधान मंत्री जी को वे सदन की भावना से अवगत करा देंगी। तो उन्होने अवगत कराया कि नहीं कराया।

दो महीने बीत गए है, उनको जरा बताने तो दीजिए। व्हाट इज द रिएक्शन?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Sir, I had said that I would send the proceedings of that day to the Prime Minister... *(Interruptions)...*

THE SATYA PRAKASH MALAVIYA: No, no; you said 'your feelings', not the proceedings.

SHRI DIGVIJAY SINGH: You said 'your feelings'.

SHRIMATI MARGARET ALVA: "Feelings" is the record of the House. I cannot convey them in any other way, except through the record of what was said in the House. 1 said that I would send the entire proceedings of the day, which was done that very day.

RE: NEED TO IMPROVE WORKING AND LIVING CONDITIONS OF CONTRACTUAL AND CONSTRUCTION WORKERS

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, I wish to draw the attention of the House and the Government to the increasing distress of contract workers and the workers connected with the construction industry whose number is around 20 million, with poor service and living conditions. Whatever social security measures are granted to them have not been implemented. Sir, both the contract workers and the construction workers are governed by the Minimum Wages Act of 1948 so far as their wages are concerned. Since 1948, the Minimum Wages Act has not been revised, has not been changed despite the fact that the Committee of the Labour Ministers made several recommendations in its Report of 1990. The service conditions of Contructor workers are governed by the Contract